



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्य में 26 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्वास एवं लोकार्पण एवं

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन

मुख्य अतिथि

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

गरिमामय उपस्थिति

श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे
माननीय राज्यपाल, राजस्थान

श्री अश्विनी वैष्णव
माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार

शिलान्वास

- गोटन - साथिन (पीपाड़) राज्य राजमार्ग सं. 86-बी के विकास का कार्य
- अमृत 2.0 के अंतर्गत पाली, मारवाड़ जंक्शन, बाली, रानी, सोजत सिटी, फालना, सादड़ी में शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के कार्य एवं जायका वित्त पोषित जिला झुंझुनूं (285 गांव) व सूरजगढ़ तथा उदयपुरवाटी शहर में पेयजल आपूर्ति कार्य
- डॉ. करणीसिंह लिपट नहर के गिरजासर, गडियाला माइनर, देवड़ा वितरिका, कोलायत वितरिका, नखत बन्ना माइनर और उप-माइनर के कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई प्रणाली का विकास

लोकार्पण

- अजमेर, ब्यावर, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, बाँसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, सीकर, टोंक एवं जालोर जिलों के 14 राज्य राजमार्गों के 12 विकास कार्य
- बाँसवाड़ा जिले में माही सिंचाई परियोजना की 10 नहर प्रणालियों के पुनर्वास के कार्य
- राजपुरा (बीकानेर) एवं सराड़ा (सलूम्बर) में 132 केवी जीएसएस लाइनें
- नाथद्वारा (राजसमन्द), प्रतापगढ़, पालड़ी (भीलवाड़ा) एवं धौलपुर में नर्सिंग कॉलेज

22 मई, 2025 | प्रातः 10:30 बजे | स्थान - पलाना, बीकानेर

विकास पथ पर राजस्थान

अमेरिका से भारत भेजे गये प्रत्येक 1000 डॉलर पर अब पचास डॉलर का नया टैक्स लगेगा

जैसा कि विदित ही है, अमेरिका से भारतीय मूल के 45 लाख लोग, अपने वृद्ध माँ-बाप के लिये, बच्चों की शिक्षा व अन्य इमरजेंसियों के लिए, प्रति वर्ष लगभग 100 बिलियन डॉलर भेजते हैं

-सुकमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। अमेरिकी प्रशासन के एक नए लैजिस्लेटिव प्रोजेक्ट (विवायी प्रस्ताव) के अंतर्गत भारतीय मूल के लोगों और नई दिल्ली के निवासियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। यह विवायी फ्लूट विल एक्ट" नाम के इस प्रस्ताव में अमेरिका से विदेश भेजी जाने वाली रकम पर 5 प्रतिशत प्रत्येक टैक्स लगाने की चिंता है। यह कदम भारतीय प्रवासी और उनके देश में विदेशीयों के बीच एक महत्वपूर्ण फायदानीशयल लाइफलाइन को झटका दे सकता है। यदि यह कानून बनता है, तो इसका असर भारत के शहरों से लेकर गांवों तक के रेल बूजारों पर पड़ेगा और भारत की व्यापक आधिकारियों तक पहुंचेगा। यह प्रत्यावरण टैक्स सभी गैर-अमेरिकी नागरिकों द्वारा अपने देशों में भेजी जाने वाली राशि पर लागू होगा,

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- अब इस 5 प्रतिशत के नये प्रस्तावित टैक्स से, इस रकम में लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की कमी होने का अंदाज़ा है।
- गाँव व छोटे-छोटे शहरों में बसे परिवारों के लिए अमेरिका से उनके बच्चों द्वारा भेजी गई यह रकम जीवन-दायिनी का काम करती थी। अतः अमेरिका से आने वाले पैसे की "फ्रीकॉर्सी" कम हो जायेगी या "अमाउंट" कम हो जाएगा।
- अतः, भारी संभवाना है कि अब अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीय, अपने परिवार को भेजने वाले पैसे को हवाला या अन्य "अव्यवस्थित व गैर कानूनी" रास्ते से भेजने लगेंगे।
- भारत में विदेश से (अमेरिका से) आने वाली रकम घटने से भारत का विदेशी मुद्रा का कोष (रिजर्व) भी लगातार कम होगा।
- साथ ही भारत अमेरिका के बीच संबंधों में दरार भी आ सकती है, क्योंकि ये अप्रवासी भारतीय अपनी मेहनत से अमेरिका की इकॉनॉमी को समृद्ध तो करते ही हैं, अपने भारत स्थित परिवारों का लालन-पालन भी करते हैं और उनकी इस जायज़ आय को बाधित करने से दोनों देशों के बीच तनाव तो आयेगा ही।
- पर, ट्रूप्स इस कदम से अपने गोल बैंक को तो खुश कर रहे हैं, जो कि "अमेरिका फर्स्ट" नाम से विश्वास करते हैं तथा भारी संख्या में विदेशीयों के अमेरिका आने को पसंद नहीं करते।

सुप्रीम कोर्ट ने अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत पर रिहा किया

पर, साथ ही कठाक्ष भी किया कि जब देश युद्ध में फंसा है तथा दुष्ट सङ्कोचों पर धूम रहे हैं, तब हमें संगठित रहना चाहिए या सत्ती लोकप्रियता की फिराक में "सांप्रदायिक टिप्पणियाँ" करनी चाहिए

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका युनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी को जमानत दे दी, जिन्हें 18 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर विवादायक डोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लोकान् सुप्रीम कोर्ट ने जो पर रोक लगाने वाले इकाई को फिराक कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी दी, पर ऑपरेशन सिंदूर को "डॉग विस्टिंग" और "सत्ती लोकप्रियता पाने का प्रवासी" बताने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

बाटा ने कैरी बैग के 6 रु. वसूले, 61 हजार का जुमाना भरना पड़ा

जयपुर, 21 मई। जिला उपभोक्ता आयोग, तुरीय ने ग्राहक को जूँझे के साथ कंपनी का नाम लिया करी बैग देने के बदले 6 रुपए वसूले माना है। इनके साथ ही, आयोग ने बाटा इंडिया पर 61 हजार रुपए हजारना लगाते हुए उन्हें दिवेश दिया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज

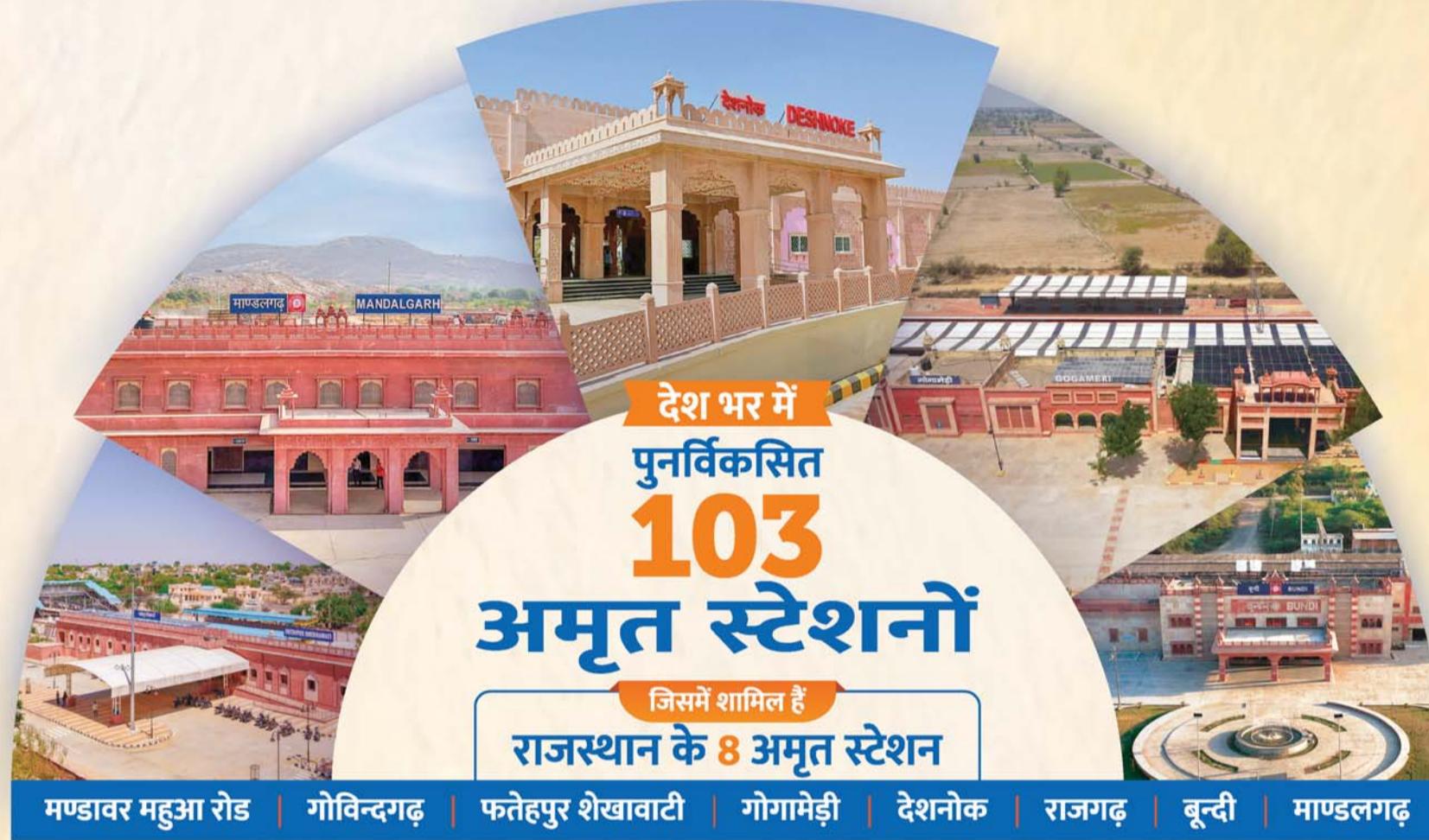
मोहन माशुर व सदस्य पवन कुमार भारद्वाज ने यह आदेश नीता पारिक के परिवार पर दिया आयोग ने कहा कि कैरी बैग पर बाटा का विज्ञापन था और ऐसे में वह निशुल्क होना चाहिए था।

मामले के अनुसार विवारी को प्रिवेट व्यापारी के नाम से अपने दिवेश दिया गया है कि वह अपरिवारी से कैरी बैग के बदले 6 रुपए 9 प्रतिशत व्याज



विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

राजस्थान की जनता के लिए
₹26,000 करोड़ के उपहार



एवं
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत सेक्टर की
विभिन्न परियोजनाओं
का

उद्घाटन

चूरू - सादुलपुर रेल खंड का दोहरीकरण (58 कि.मी.)

एवं

विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर्स तथा राजस्थान सरकार की
विभिन्न परियोजनाओं का

शिलान्यास

बीकानेर और मुंबई
के बीच
देशनोक रेलवे स्टेशन
से नई एक्सप्रेस ट्रेन का

शुभाराम

विद्युतीकृत रेल खंड

सूरतगढ़ - फलोदी | फुलेरा - डेगाना | उदयपुर - हिंमतनगर
फलोदी - जैसलमेर | समदड़ी - बाड़मेर

एवं
सड़क परिवहन और राजमार्ग सेक्टर की
विभिन्न परियोजनाओं का
राष्ट्र को समर्पण

नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री

के कर कमलों द्वारा

गुरुवार 22 मई, 2025 | प्रातः 10:30 बजे | देशनोक, बीकानेर (राजस्थान)

गरिमामयी उपस्थिति

हरिभाऊ किसनराव बागडे

राज्यपाल, राजस्थान

ओम बिरला

अध्यक्ष, लोक सभा

भजन लाल शर्मा

मुख्यमंत्री, राजस्थान

अश्विनी वैष्णव

केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

भूपेन्द्र यादव

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

गजेन्द्र सिंह शेखावत

केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

अर्जुन राम मेधवाल

केन्द्रीय विद्यि और न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री



पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों की मुख्य विशेषताएँ

- सिटी सेंटर के रूप में विकास - रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, विश्राम कक्ष, विशाल परिसंचारी क्षेत्र आदि जैसी सुविधाएं
- विरासती विकास भी स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन
- अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वारा, बेहतर पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, लाउंज, प्रतीक्षालय, ट्रैवलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं
- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण से ये स्टेशन बनेंगे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र
- स्टेशनों के डिज़ाइन में ऊर्जा दक्षता और हरित उपायों को प्राथमिकता, जिससे न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव



अन्य परियोजनाओं के लाभ

- चूरू-सादुलपुर रेल लाइन की डबलिंग से ट्रेन संचालन में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और स्थानीय व्यापार में वृद्धि
- एक्सप्रेस ट्रेन से व्यापारियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ
- विद्युतीकृत रेल खंडों से ऊर्जा की बचत